



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 24, 2017/वैशाख 4, 1939

No. 113]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 24, 2017/VAISAKHA 4, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाठनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2017

मामला सं. ओआई/24/2017

**विषय:** इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और सऊदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेचुरेटिड फैटी अल्कोहल्स" के आयातों के संबंध में पाठनरोधी जांच की शुरूआत।

**फा. सं. 14/51/2016-डीजीएडी.**—मैसर्स वीवीएफ इंडिया लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष, समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटिट वस्तुओं पर पाठनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" कहा गया है) के अनुसरण में इंडोनेशिया, थाइलैंड और सऊदी अरब (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सेचुरेटिड फैटी अल्कोहल्स के आयातों पर पाठनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

**क. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि "सिंगल, ब्लैंड और अनब्लैंडिड (जिनमें ब्रांच्ड आइसोमर शामिल नहीं है) सहित सी-8, सी-10, सी-12, सी-14, सी-16 और सी-18 की लंबाई के कार्बन चैन सहित सेचुरेटिड फैटी अल्कोहल्स, जिनमें सी12-सी14, सी12-सी16, सी12-सी18, सी16-18 और सी14-सी16 की कार्बन लंबाई के संयोजन वाले ब्लैंडस" शामिल हैं, जिन्हें इसके बाद वर्तमान अधिसूचना में बताए गए देशों से "संबद्ध वस्तुओं" के रूप में संदर्भित किया गया है, के आयात पाटिट कीमतों पर भारतीय बाजार में आ रहे हैं और ऐसे आयात घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे समान उत्पाद के लिए क्षति का कारण बन रहे हैं। अनसेचुरेटिड फैटी अल्कोहल्स को वर्तमान जांच के दायरे से बाहर रखा गया है।

3. ऊपर उल्लिखित संबद्ध वस्तुएं एलिफैटिक अल्कोहल्स हैं और सेचुरेटिड और अनसेचुरेटिड रूप में घटित होती है। उत्पाद के लिए सामान्य रसायन फॉर्मूला सीएच2ओएच(2एन+1)सीएच2ओएच है जहां "एन" की वैल्यू 7 से 17 के बीच है। फैटी अल्कोहल की स्थापक सामग्रियां डेकेन-1-01, एन-डोडेकानोल, ट्रिआडिकानोल, हैक्साडिकेन 1-01, ओक्टाडिकनोल आइकोसन-1-01, इकोसन-1-01 हैं। इन अल्कोहल्स को कार्बन एटम की संख्या के अनुसार समूहीकृत किया जा सकता है और इनकी सर्वाधिक सामान्य लम्बाई सी-12, सी-14 और उसके ब्लैंड हैं।

4. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन प्राकृतिक फैट और तेलों के रूपांतरण के जरिए मिथाइल एस्टर या वैक्स एस्टर को कम करके किया जाता है। इस प्रयोजन हेतु आम तौर पर पाम करनेल ऑयल का प्रयोग किया जाता है, हालांकि, स्थानीय तेलों का प्रयोग भी किया जा सकता है। उत्पादन प्रक्रिया वेजीटेबल ऑयल्स को स्पिलिट करने से आरंभ होती है जैसे कि क्रूड पाम करनेल ऑयल ("सीपीकेओ") जो कि सतत प्रक्रिया के रूप में उच्च तापमान और दबाव पर रखा जाता है। वेजीटेबल ऑयल्स/फैट (अव्याच) मूल रूप से फैटी एसिड का ट्रिगलिसराइड्स है जो फैट स्पिलिटिंग के रूप में सामान्यतः परिचित हाइड्रोलिसिस रिएक्शन द्वारा फैटी एसिड और ग्लिसरोल में परिवर्तित हो जाती है। क्रूड फैटी एसिड को तब और संसाधित किया जाता है जिसके द्वारा वे उच्च तापमान और वैक्यूम पर सादे/फ्रैक्शनल डिस्टीलेशन के अध्यधीन होते हैं। यह प्रक्रिया के अनुसरण में एस्टेरिफिकेशन होता है जो वैक्स एस्टर तब हाइड्रोजेनेशन के अध्यधीन होता है। यह हाइड्रोजेनेशन प्रतिक्रिया निर्धारित ब्रेड कॉपर केटालिस्ट की उपस्थिति में होती है जिसका परिणाम क्रूड फैटी अल्कोहल में होता है। क्रूड फैटी अल्कोहल को तब डिस्लिड किया जाता है जिससे तैयार उत्पाद प्राप्त होता है।

5. संबद्ध वस्तुएं फ्लैक्स, पेस्टिल्स और द्रव्य के रूप में बेची जाती हैं। ये मुख्य रूप से व्यक्तिगत देखभाल, घर की देखभाल, फार्मास्यूटिकल और कृषि संबंधी कार्यों और उपयोग के लिए, सरफेक्टेंट के निर्माण के लिए प्रयोग की जाती हैं। ये चमड़े, वस्त्र, घर, लुगदी, पेपर, पेट्रोलियम उत्पाद, फाइन रसायन, रबड़ उत्पादों, प्लास्टिक और फैब्रीकेटिड उत्पादों की वस्तुओं के संसाधन में भी प्रयुक्त होते हैं। इसके अन्य उपयोगों में साल्वेट और डिग्रीजिंग प्रयोजन के रूप में खनन, अपतटीय प्रचालनों, निर्माण कार्य शामिल हैं। सी-12-सी16 फैटी अल्कोहल्स के ब्लैंड्स का इसके अतिरिक्त सिथेटिक माध्यम या फ्रीजरोधी और पायस एंजेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह पेंट, लुब्रिकेंट्स, सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादन एवं खाद्य सामग्री को तैयार करने आदि में भी प्रयुक्त होता है।

6. अनब्लैंडिड फैटी अल्कोहल्स को शीर्ष 2905.17 या 2905.19 के तहत वर्गीकृत किया गया है जबकि ब्लैंडिड अल्कोहल को शीर्ष 3823.70 के तहत वर्गीकृत किया गया है। शीर्ष 3823.70 के अंतर्गत, उनका निम्नलिखित टैरिफ प्रविष्टियों के तहत आयात किया जाता है:

- (a) 3823.70.10
- (b) 3823.70.20
- (c) 3823.70.40
- (d) 3823.70.90

उपर्युक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

7. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच सामग्री में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। संबद्ध वस्तुएं याचिकार्ता द्वारा उत्पादित उत्पादों के प्रति वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से वैकल्पिक हैं और समान या समकक्ष उपयोगों के लिए सरफेक्टेंट और अन्य उत्पादों के उन्हीं प्रयोक्ताओं/विनिर्माताओं द्वारा खरीदा और बेचा जाता है। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थी, प्राधिकारी ने भारत में आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" माना है।

**ख. घरेलू उद्योग और स्थिति**

8. आवेदन मैसर्स वीवीएफ इंडिया लि. (जिसे वर्तमान अधिसूचना में आगे "घरेलू उद्योग" या "आवेदक" कहा गया है) द्वारा दायर किया गया है। आवेदक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से किसी प्रकार संबंधित नहीं है। आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। मामले के तथ्य स्थापित करते हैं कि आवेदक को नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर पात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए।

9. भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक और उत्पादक अर्थात् मै. गोदरेज इंडस्ट्रीज लि. है। तथापि, आवेदक ने दावा किया है कि मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लि. ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और अतः उसे घरेलू उद्योग का भाग माने जाने के लिए पात्र नहीं है। अतः आवेदक ने निवेदन किया है कि वह पात्र घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत लेखा बताते हैं। आवेदक ने मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लि. के उत्पादन के अनुमान उपलब्ध कराए हैं। उन अनुमानों के आधार पर यह देखा गया है कि चाहे, यदि मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लि. को पात्र घरेलू उद्योग माना गया है, आवेदक घरेलू उत्पादक का 50 प्रतिशत से अधिक

उत्पादन पर आधिपत्य रखते हैं। इस प्रकार, आवेदक, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ नियम 2(ब) में यथा परिभाषित शर्तों के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग स्थापित होता है। आवेदक संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के प्रमुख समानुपात का उत्पादन करता है और इसलिए नियमावली के नियम 5(3) की शर्तों में आवेदन करने की शर्तों को पूरा करता है। आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया गया माना गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा जा सकता है कि मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लि. ने अनुरोध किए जाने के बावजूद कोई सूचना नहीं दी है।

#### **ग. जांच किए जाने वाले देश**

10. वर्तमान जांच इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और सऊदी अरब ("संबद्ध देशों" के रूप में संदर्भित) से सेचुरेटिड फैटी अल्कोहल के कथित पाटित आयातों के संबंध में है। इन देशों से आयात की मात्रा निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है। ऊपर उल्लिखित देशों के अतिरिक्त, अन्य देशों से आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमा से कम है।

#### **घ. पाठन का साक्ष्य**

11. आवेदक ने निवेदन किया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमतों पर पब्लिक डोमेन में विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता के अभाव में, संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य का अनुमान, उत्पादन लागत के अनुमान, कझी सामग्री और सुविधाओं की लागत और घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत को ध्यान में रखते हुए और विधिवत रूप से समायोजित विक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय जमा, और तरक्सिंगत लाभ पर विचार करते हुए लगाया गया है।

12. आवेदक ने जांच और पीओआई की अवधि के लिए कारखानागत निर्यात कीमत का दावा डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़े और समुद्री भाड़ा, समुद्री प्रभाव, पत्तन व्यय, कमीशन, बैंक प्रभाव और अंतर्देशीय माल-भाड़ा व्यय के कारण उचित समायोजन के पश्चात किया है।

13. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतें दर्शाती हैं कि इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं कि संबद्ध वस्तुएं सामान्य मूल्य की तुलना में उच्च कीमत पर भारत को संबद्ध देशों से निर्यात की जा रही हैं और पाठन मर्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है।

#### **ड. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य**

14. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से उल्लेखनीय क्षति हुई है जैसा कि विभिन्न मापदंडों द्वारा दर्शाया गया है जैसे उत्पादन, मूल्य ह्रास, कीमत कटौती, कम कीमत पर विक्री और मूल्य तालिका, लाभप्रदता, नियोजित पूँजी पर आय और घरेलू उद्योग के नकदी प्रवाह पर परिणामी विपरीत प्रभाव पड़ना। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग और बाजार में हिस्सा पहले दर्ज किए गए काफी निम्न स्तरों पर है। अतः पाठनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित बताने के लिए संबद्ध देशों से कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही "क्षति" के पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं।

#### **च. जांच की शुरूआत**

15. उक्त नियमावली को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाठनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाठन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाठन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं और कथित पाठन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाठनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई "क्षति" को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। तदनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के पैरा 5 के अनुसार, कथित पाठन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं।

#### **छ. जांच की अवधि (पीओआई)**

16. आवेदक ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 01 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2016 (15 महीने) प्रस्तावित की है। तथापि, मै. वीवीएफ इस अवधि के दौरान 100 प्रतिशत ईओयू था। इस अवधि के दौरान प्राधिकारी ने जांच की अवधि 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 (12 महीने) विचारित की है ताकि अत्यधिक अद्यतन डाटा के आधार पर पाठन और क्षति संबंधी विश्लेषण किया जा सके। क्षति जांच की अवधि में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-16 तथा जांच की अवधि (01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017) के आंकड़े शामिल हैं।

#### **ज. सूचना प्रस्तुत करना**

17. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातिकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में उत्पादन से संबंधित ज्ञात आयातों व प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं निर्धारित ढंग से समस्त संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें जिससे प्राधिकारी समयबद्ध ढंग से समुचित निर्धारण कर सकें।

### निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय,  
वाणिज्य विभाग, चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,  
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

[dgad.india@gov.in](mailto:dgad.india@gov.in)

18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति (जो प्राधिकारी की वेबसाइट ([www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in)) से डाउनलोड किया जा सकता है) से प्रस्तुत कर सकता है।

**अ. समय सीमा**

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना की तारीख से दो सप्ताह के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के चालीस (40) दिनों के भीतर प्रश्नावली के अपने उत्तर तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। सूचना हार्ड प्रति के साथ ही सॉफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

20. निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इस सूचना के पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर अपने उत्तर अलग-अलग प्रस्तुत करने के लिए अलग-अलग सूचित किया जा रहा है।

21. वर्तमान जांच और सुनवाई से संबंधित कोई भी सूचना और अनुरोध लिखित में दिया जाना चाहिए ताकि वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच सके। यदि निर्धारित समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

22. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

**ब. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

23. प्रश्नावली के उत्तर सहित गोपनीय आधार पर प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उनके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को किए गए अनुरोधों को अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना होगा जिसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उनकी मूल प्रति के साथ दो-दो (2) प्रतियों में दोनों अंशों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

24. दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

25. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना हो सकती है जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या अन्य सूचना जिसे ऐसी सूचना का प्रदाता व्यापार संबंधी सूचना होने का दावा करता है जिसके प्रकटन से ऐसी सूचना के प्रदाता का वाणिज्यिक हित प्रतिकूलतः प्रभावित होंगे। ऐसा सूचना जिसके स्वरूप द्वारा गोपनीय होने का दावा किया जाता है या अन्य कारणों से जिसकी गोपनीय होने का दावा किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से गोपनीय और गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदान को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। यदि सूचीबद्ध करना संभव नहीं है तो सूचना को सारांश रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी सूचना पर निर्भर करते हुए, जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसा सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है। सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी

कर सकते हैं। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकारी के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### **ट. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

28. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

#### **ठ. असहयोग**

29. यदि कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं, जैसा भी वे उचित समझते हैं।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

## **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)**

### **INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th April, 2017

Case No. OI/24/2017

**Subject: Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of “Saturated Fatty Alcohols” originating in or exported from Indonesia, Malaysia, Thailand and Saudi Arabia**

**F.No. 14/51/2016-DGAD.**—M/sVVF India Limited(hereinafter referred to as “the applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as “the Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Act”) and Customs Tariff(Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as “the Rules”) for imposition of anti-dumping duty on imports of Saturated Fatty Alcohols, originating in or exported fromIndonesia, Malaysia, Thailand and Saudi Arabia (hereinafter also referred to as the “subject countries”).

#### **A. Product allegedly being dumped and like Article**

2. The applicant have alleged that the imports of“Saturated Fatty Alcohols with carbon chain length of C8, C10, C12, C14, C16, and C18 including single, blends and unblended (not including branched isomers) which includes blends of a combination of carbon chain lengths, C12-C14, C12-C16, C12-C18, C-16-18 and C14-C16”, hereinafter also referred to as the “subject goods”from the countries named in the present notification are entering the Indian market at dumped prices and such imports are causing injury to the like product being produced by the domestic industry.Unsaturated fatty alcohols are excluded from the scope of the present investigations.
3. The above mentioned subject goodsare aliphatic alcohols and occur in saturated and unsaturated forms. The general chemical formula for the product is  $C_nH(2n+1)CH_2OH$ , where the value of "n" ranges from 7 to 17. The constituent materials of fatty alcohols are Decan-1-ol, N-Dodecanol, Tetradecanol, Hexadecan-1-ol, Octadecanol, Eicosan-1-ol, Ecosan-1-ol. These alcohols can be grouped according to the number of carbon atoms, and most common lengths are C12, C14 and blends thereof.
4. The subject goods are produced by the reduction of methyl ester or wax ester, through the conversion of natural fats and oils. For this purpose, mostly palm kernel oil is used, although certain local oils may also be used. The production process starts with splitting of vegetable oils, such as Crude Palm Kernel Oil ("CPKO"), which is carried out at high temperature and pressure, as a continuous process. The vegetable oils/fats (non-edible) are basically triglycerides of fatty acids, which get converted to fatty acids and glycerol by the hydrolysis reaction commonly known as Fat Splitting. The crude fatty acids are then processed further, whereby they are subjected to plain/fractional distillation, at a high temperature and vacuum. This process is followed by esterification resulting

from a reaction between fatty acid and fatty alcohol in an inert atmosphere to make wax ester. Pure wax-ester is then subjected to hydrogenation. This hydrogenation reaction takes place in the presence of fixed bed copper catalyst, resulting in crude fatty alcohol. The crude fatty alcohol is then distilled and purified, from which the finished product emerges.

5. The subject goods are sold in the form of flakes, pastilles, and liquids. They are mainly used for the manufacture of surfactants, for personal care, home care, pharmaceutical and agriculture related end applications. They are also used in relation to processing of articles of leather, textile, fur, pulp, paper, petroleum products, fine chemicals, rubber products, plastics and fabricated metal products. Other applications include mining, offshore operations, construction work, as a solvent and for degreasing purposes. Blends of C12-C16 fatty alcohols are additionally used as synthetic intermediate or anti-freeze and as emulsifying agent. It also finds use in the production of paints, lubricants, cosmetics, food preparations, etc.
6. Unblended fatty alcohols are classified under heading 2905.17 or 2905.19, while blended alcohols are classified under heading 3823.70. Under the heading 3823.70, they are imported under the following tariff entries:
  - (a) 3823.70.10
  - (b) 3823.70.20
  - (c) 3823.70.40
  - (d) 3823.70.90

The customs classification above is indicative only and in no way binding on the scope of the product under consideration in this investigation.

7. The applicant has claimed that there are no known material differences between the subject goods exported from the subject countries, and that produced by the domestic industry. The subject goods are commercially and technically substitutable to the products produced by the petitioner; and are bought and sold by the same consumers / manufacturers of surfactants and other products, for the same or similar applications. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority has treated the subject goods produced by the applicant domestic industry in India as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

#### **B. Domestic Industry & Standing**

8. The application has been filed by M/s VVF India Limited (referred to as “the Domestic Industry” or “the applicant” in the present notification). The applicant is not related to the exporters or importers of the alleged dumped article. The applicant has not imported the subject goods during the period of investigation. The facts of the case establish that applicant should be considered eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b).
9. There is one more producer of the subject goods in India, that is, M/s Godrej Industries Limited. However, the applicant has claimed that M/s Godrej Industries Limited has imported the subject goods during the period of investigation, and thus, is not eligible to be treated as a part of domestic industry. Thus, the applicant has submitted that they account for 100% of the eligible domestic production. The applicant has provided estimates of production of M/s Godrej Industries Limited. On the basis of such estimates, it is seen that even if M/s Godrej Industries Limited is treated as eligible domestic industry, the applicant commands more than 50% of the the domestic production. Thus, the applicant constitutes domestic industry within the meaning of the term as defined in Rule 2(b) for the purpose of present investigation. Applicant accounts for a major proportion of the domestic production of the subject goods and therefore, commands the standing to file the application in terms of Rule 5(3) of the Rules. The application is deemed to have been by the domestic industry.

#### **C. Countries to be investigated**

10. The present investigation is in respect of alleged dumped imports of Saturated Fatty Alcohol from Indonesia, Malaysia, Thailand and Saudi Arabia (referred to as “the subject countries”). The volume of imports from these countries is above the de-minimis limit prescribed. Apart from the aforementioned countries, the volume of imports from other countries is below de-minimis limits.

#### **D. Evidence of Dumping**

11. The applicant has submitted that in the absence of availability of reliable information in the public domain on domestic prices of the subject goods in the subject countries, the normal values in the subject countries have been determined on the basis of estimates of cost of production, taking into account cost of raw materials and utilities, and conversion costs of the domestic industry, and duly adjusted to include selling, general & administration expenses, and a reasonable profit.

12. The applicant has claimed ex-factory export price on the basis of transaction wise import data procured from International Business Information Services (IBIS), a secondary source, for the period of investigation and after due adjustments on account of ocean freight, marine charges, port expenses, commission, bank charges and inland freight expenses.
13. The normal values and export prices determined show that there is sufficient *prima facie* evidence that the subject goods are being exported from the subject countries to India at a price significantly higher than normal value and the dumping margins are above de-minimis.

**E. Evidence of Injury and Causal Link**

14. The applicant has claimed that domestic industry has suffered material injury from dumped imports as shown by various parameters such price depression, price undercutting, price underselling and consequent adverse impact on production, inventories, profitability, return on capital employed and cash flow of the domestic industry. The applicant has claimed that domestic industry has earlier suffered serious injury due to increased imports of the subject goods in India and the domestic industry was in the process of recovering from the serious injury earlier suffered. The exporters in subject countries have however started dumping of the product after imposition of safeguard duty, which has prevented recovery of the domestic industry and the domestic industry continues to suffer injury. Production, capacity utilisation and market share of the domestic industry in the investigation period are at a level below the levels registered earlier before surge in imports. The applicant has also submitted that the present safeguard duty shall expire in Feb., 2017 and the domestic industry shall suffer intensified injury once the present safeguard duty ceases. There is sufficient *prima facie* evidence of ‘injury’ being suffered by the domestic industry caused by alleged dumped imports from the subject countries to justify initiation of an antidumping Investigation.

**F. Initiation of the Investigation**

15. Having regard to the above Rules, the Authority finds sufficient *prima facie* evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury, to justify initiation of an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry. Accordingly, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules.

**G. Period of Investigation (POI)**

16. The applicant has proposed the period of investigation (POI) for the purpose of present investigation from 1<sup>st</sup> April, 2015 to 30<sup>th</sup> June, 2016 (15 months). However, M/s VVF was 100% E.O.U. during this period Authority has considered the POI as 1<sup>st</sup> April, 2016 to 31<sup>st</sup> March, 2017 (12 months) so as to undertake dumping and injury analysis on the basis of most recent data. The injury investigation period covers the data of previous three years, i.e. 2012-13, 2013-14, 2014-15 and the period of investigation (1<sup>st</sup> April, 2016 to 31<sup>st</sup> March, 2017).

**H. Submission of information**

17. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address, so as to enable the Authority make appropriate determinations in a timely manner:

The Designated Authority,  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,  
Department of Commerce  
4th Floor, Jeevan Tara Building,  
5 Parliament Street,  
New Delhi -110001 dgad.india@gov.in

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner (downloadable from the website of the Authority at [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in)) within the time limit set out below.

**I. Time limit**

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter within 2 weeks from the date of this notification and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.
20. The exporters/importers and other interested parties, being notified individually, may file their responses within forty days (40 days) from the date of intimation to be addressed to them separately.
21. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.
22. If no information is received from an interested party within the prescribed time limit, or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record, in accordance with the Rules.

**J. Submission of Information on Non-Confidential basis**

23. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority, including questionnaire response on confidential basis, are required to file a non-confidential version of the submissions made, which will be made available to all other interested parties to make their comments. Soft copies of both the versions are required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each.
24. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked so at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
25. The confidential version may contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as business proprietary information, disclosure of which will adversely affect the commercial interests of the supplier of such information. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out. In case indexation is not feasible, the information may be summarized, depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted, or if the supplier of the information is either not willing to make the information public, or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**K. Inspection of Public File**

28. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties to the investigation.

**L. Non-cooperation**

29. In case, any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr. INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority